# The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27—अक्तूबर 3, 2014 (आश्विन 5, 1936)

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27—OCTOBER 3, 2014 (ASVINA 5, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### विषय-सूची पुष्ठ सं. पुष्ठ सं. भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की आदेश और अधिसूचनाएं..... गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं..... (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोडकर) भारत सरकार के प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकत पाठ (ऐसे पाठों को छोडकर जो भारत अधिसूचनाएं. ..... 875 के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों होते हैं)..... और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी नियम और आदेश..... अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नितयों, भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. ..... 1677 महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... अधिसूचनाएं. ...... 1177 भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और के बिल तथा रिपोर्ट. ..... डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं...... प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों छोडकर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और और नोटिस शामिल हैं...... 4175 उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 1183 भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को को दर्शाने वाला सम्पुरक. .....

# **CONTENTS**

	Page No.		Page No.
PART I—Section 1—Notificatiosns relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the	110.	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)  Part II—Section 3—Sub-Section (iii)—Authoritative	*
Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court		texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than	
Part I—Section 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the		Administration of Union Territories)  Part II—Section 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
Ministry of Defence		PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by	
PART II—Section 1—Acts, Ordinances and Regulations PART II—Section 1A—Authoritative texts in Hindi	*	Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1177
language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	Part III—Section 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
Committee on Bills	*	Part III—Section 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the		Part III—Section 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	4175
Administration of Union Territories)  PART II—Section 3—Sub-Section (ii)—Statutory  Orders and Notifications issued by the	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1183
Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		Part V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

<sup>\*</sup>Folios not received.

## भाग I — खण्ड 1

# [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 2014

### संकल्प

विषय: देश के भूजल संसाधन के समग्र पुन: आकलन के लिए केन्द्र स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन।

सं. टी-13014/3/2014-जीडब्ल्यू--पूरे देश के लिए राज्य-वार वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन का पिछला आकलन भूजल संसाधन आकलन सिमित (जीईसी)-97 की पद्धित के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार किया गया था। तब से देश के विभिन्न स्थानों में भूजल परिदृश्य में कई परिवर्तन हुए हैं। तदनुसार, पूरे देश में भूजल संसाधन के पुन: आकलन (31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार) के समग्र पर्यवेक्षण के लिए एतद्द्वारा एक केन्द्रीय स्तरीय विशेषज्ञ समूह गठित किया जाता है। विशेषज्ञ समूह का संघटन और विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

### (1) संघटन :

(i)	अध्यक्ष, सीजीडब्ल्यूबी	अध्यक्ष
(ii)	सदस्य (आरएम), सीडब्ल्यूसी	सदस्य
(iii)	सदस्य (डब्ल्यू पी एवं पी), सीडब्ल्यूसी अथवा प्रतिनिधि	सदस्य
(iv)	सदस्य (एसएम एवं एल), सीजीडब्ल्यूबी	सदस्य
(v)	सदस्य (एसएएम), सीजीडब्ल्यूबी	सदस्य
(vi)	सदस्य (ईडी एवं एमएम), सीजीडब्ल्यूबी	सदस्य
(vii)	सदस्य (आरजीआई), सीजीडब्ल्यूबी	सदस्य
(viii)	अपर महानिदेशक (सांख्यिकी), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
(ix)	प्रमुख महाप्रबंधक, नाबार्ड	सदस्य
(x)	निदेशक , एनआईएच, रूड़की अथवा प्रतिनिधि	सदस्य
(xi)	योजना आयोग का प्रतिनिधि	सदस्य
(xii)	संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय	सदस्य
(xiii)	संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य
(xiv)	संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय (वाटरशेड विकास कार्यक्रम)	सदस्य
(xv)	संयुक्त सचिव, पेयजल आपूर्ति विभाग	सदस्य
(xvi)	संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य
(xvii)	आईआईटी, दिल्ली (जल संसाधन अनुभाग)-सिविल अभियांत्रिकी विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
(xviii)	मुख्य अभियंता (मुख्यालय), एनडब्ल्यूडीए अथवा प्रतिनिधि	सदस्य
(xix)	तकनीकी विशेषज्ञ ( डब्ल्यूएम), एनआरएए, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	सदस्य

(xx)	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
(xxi)	भारतीय भूगर्भ विज्ञान सर्वेक्षण का प्रतिनिधि	सदस्य
(xxii)	प्रभारी सचिव, जल संसाधन, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(xxiii)	प्रभारी सचिव, जल संसाधन, पंजाब	सदस्य
(xxiv)	प्रभारी सचिव, जल संसाधन, महाराष्ट्र	सदस्य
(xxv)	प्रभारी सचिव, जल संसाधन, आंध्र प्रदेश	सदस्य
(xxvi)	प्रभारी सचिव, जल संसाधन, राजस्थान	सदस्य
(xxvii)	प्रभारी सचिव, जल संसाधन, मध्य प्रदेश	सदस्य
(xxviii)	प्रभारी सचिव, जल संसाधन, गुजरात	सदस्य
(xxix)	प्रभारी सचिव, जल संसाधन, पश्चिम बंगाल	सदस्य
(xxx)	सिविल अभियांत्रिको विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बॅंगलोर का प्रतिनिधि	सदस्य
(xxxi)	सदस्य (टीटी एवं डब्ल्यू क्यू), सीजीडब्ल्यूबी	सदस्य सचिव

समिति आवश्यक समझने पर किसी अन्य सदस्य (सदस्यों) को नियुक्त कर सकती है।

### (2) विचारार्थ विषय:

- (i) संदर्भ वर्ष 2013 के लिए संबंधित राज्य स्तरीय सिमितियों के साथ समन्वय से राज्यों के वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन का आकलन सुनिश्चित करना। सिमिति, पद्धित के अनुसार भूजल आकलन का कार्य करेगी और आकलन (आकलनों) में अधिक सटीकता प्राप्त करने के उद्देश्य से जहां भी संभव हो उन्नत प्रक्रियाओं एवं पद्धितयों को अपनाएगी।
- (ii) संबंधित राज्य स्तरीय समितियों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार राज्यों के वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन के उपयोग की स्थिति के आकलन का पर्यवेक्षण।
- (iii) दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार भूजल संसाधन के आकलन और इसके उपयोग की स्थिति के संबंध में एक राष्ट्र स्तरीय रिपोर्ट तैयार करना।
- (iv) जल संसाधन के संवर्द्धनात्मक/समग्र उपयोग के लिए इसकी आयोजना को सुविधाजनक बनाने के लिए भूजल और सतही जल आंकड़ों के एकीकरण हेतु कार्य करना।
- (v) उपर्युक्त विषयों से संबंधित कोई अन्य पहलू।

### (3) समय-सीमाः

समिति एक वर्ष के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

# (4) व्यय:

विशेषज्ञ समूह के सरकारी सदस्यों के टीए/डीए पर उस म्रोत से व्यय किया जाएगा जिससे वे अपना वेतन प्राप्त करते हैं और गैर-सरकारी सदस्यों (यदि कोई हो) के टीए/डीए का व्यय केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा।

इसे माननीय मंत्री (ज.सं., न.वि. और गं. सं.) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर. के. गुप्ता निदेशक (भूजल)

-----

## MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT, GANGA REJUVENATION

## New Delhi, the 28th August 2014

### RESOLUTION

Sub.:—Constitution of Central Level Expert Group for overall re-assessment of ground water resources of the country.

No. T-13014/3/2014-GW—The last assessment of state-wise annual replenishable ground water resources for the entire country has been made as on 31st March 2011 based on the Methodology, Ground Water Resources Estimation Committee (GEC)-97. Since then there have been changes in ground water scenario in many places of the country. Accordingly, a Central Level Expert Group is hereby constituted for over-all supervision of the re-assessment of ground water resources (As on 31st March, 2013) in the entire country. The composition and terms of reference of the Expert Group are as follows:—

# (1) Composition:

(i)	Chairman, CGWB	Chairman
(ii)	Member (RM), CWC	Member
(iii)	Member (WP&P), CWC or representative	Member
(iv)	Member (SM&L), CGWB	Member
(v)	Member (SAM), CGWB	Member
(vi)	Member (ED&MM), CGWB	Member
(vii)	Member (RGI), CGWB	Member
(viii)	Additional Director General (Stat), MOWR, RD & GR	Member
(ix)	Chief General Manager, NABARD	Member
(x)	Director, NIH, Roorkee or representative	Member
(xi)	Representative of Planning Commission	Member
(xii)	Joint Secretary, Ministry of Agriculture	Member
(xiii)	Joint Secretary, Ministry of Environment & Forests	Member
(xiv)	Joint Secretary, Ministry of Rural Development (Watershed Development Programme)	Member
(xv)	Joint Secretary, Department of Drinking Water Supply	Member
(xvi)	Joint Secretary, Ministry of Urban Development	Member
(xvii)	Representative of IIT, Delhi (Water Resources Section)- Civil Engineering Department	Member
(xviii)	Chief Engineer (HQ), NWDA or representative	Member
(xix)	Technical Expert (WM), NRAA, M/o Ag. & Coop.	Member
(xx)	Representative of India Meteorology Department	Member
(xxi)	Representative of Geological Survey of India	Member
(xxii)	Secretary In-Charge, Water Resources, Uttar Pradesh	Member
(xxiii)	Secretary In-Charge, Water Resources, Punjab	Member
(xxiv)	Secretary In-Charge, Water Resources, Maharashtra	Member
(xxv)	Secretary In-Charge, Water Resources, Andhra Pradesh	Member
(xxvi)	Secretary In-Charge, Water Resources, Rajasthan	Member
(xxvii)	Secretary In-Charge, Water Resources, Madhya Pradesh	Member
(xxviii)	Secretary In-Charge, Water Resources, Gujarat	Member
(xxix)	Secretary In-Charge, Water Resources, West Bengal	Member

(xxx) Representative of Department of Civil Engg., Indian Institute of Science (IISc), Bangalore Member

(xxxi) Member (TT&WQ), CGWB

Member Secretary

The committee may co-opt any other Member(s), if necessary.

### (2) Terms of Reference:—

- (i) To ensure the assessment of annual replenishable ground water resources of the States in coordination with the respective state level committees for the reference year 2013. The Committee will work on ground water assessments in accordance with the methodology and will adopt improved procedures and practices wherever possible for the sake of achieving greater accuracy of assessment(s).
- (ii) To supervise the estimation of status of utilization of the annual replenishable ground water resource as on 31st March 2013 of the States to be carried by the respective State level committees.
- (iii) To prepare a National level report on assessment of ground water resources and status of its utilization as on 31st March, 2013.
- (iv) To work towards integration of ground water and surface water data with a view to facilitating planning for constructive/integrated use of water resources.
- (v) Any other aspect relevant to the terms referred to above.

### (3) Time frame:—

The Committee will submit its report within one year.

# (4) Expenditure:—

Expenditure on account of TA/DA to official Members of the Expert Group will be met from the source from which they draw their salaries and that of non-official Members (if any), will be borne by the Central Ground Water Board.

This issues with the approval of Hon'ble Minister (WR, RD&GR).

### **ORDER**

Ordered that the above RESOLUTION be published in the Gazette of India for general information.

R. K. GUPTA Dir. (GW)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014 PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014 www.dop.nic.in